

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 2391 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, मार्च 24, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के निर्माण हेतु 2.00 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

PROPOSAL No.- FP/UK/OTHERS/44711/2020

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/09/140/2021/एफ०सी०/1056 दिनांक 01.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3043/12-1(2) दिनांक 06.03.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-449/भूमिह०/2022-23 दिनांक 02.02.2023 से निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र०	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	उत्तरालेख
1	In reply to point no.1 Justification provided for proposing a non site-specific project In forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category-wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van panchayat, Revenue, private, etc). The State Government is also requested to submit provide the land -use of the district and a proper justification ad to why the project could not be taken at any other place in the district.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3043/12-1(2) दिनांक 06.03.2023 से अवगत कराया गया है कि- Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 1. Certificate related for Category Wise Area of Land for District Rudraprayag is uploaded in online Proposal at additional documents and same is submitted in this letter at attachment no. 1. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. Attachment No-01
2	In reply to point no.2. Residential component is given in the component-wise break-up, which may not be allowed on forest land. State Govt. is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4in part I	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि- Residential building will not be constructed in the proposed land. Component wise breakup is revised and uploaded at para B 2.4 in part I. Document related to this query is attached in this letter at attachment 2. Attachment No-02

क्रमशः पेज 02 पर

3	In reply to point no 3, layout plan still not submitted .State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/patch separately	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अप उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि- Layout plan and activity details of each patch is submitted in this letter at attachment no 3 and same is uploaded in online proposal at additional documents. Attachment No-03
4	In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarification in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि- Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 4. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.
5	In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में हुये उल्लंघन के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.07.2015 (संलग्नक-4) को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया तत्पश्चात् वन भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिनांक 23.10.2015 (संलग्नक-5) के द्वारा संबंधित विभाग को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा प्रभागीय कार्यालय को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक-372/भूमि विषयक-2015-16 दिनांक 04.11.2015 (संलग्नक-6) के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)-2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूचना प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक-1304 /12-1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक-7) से पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-8) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-9) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रूप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।

क्रमशः पेज 03 पर

<p>6 Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि— Proper and suitable non-forest land was searched at nearby village level, revenue level and private level, but proper and suitable land was not found available for establishment of polytechnic in nearby places. A meeting was held with the village heads of the nearby 4 gram panchayats (Kunda dankot, Kolu-Bhannu, Gorna and Taday) for the availability of private land, but all the village heads said that land was not available, in relation to which all the 4 village heads signed certificate of non-availability of suitable private land was given. The certificate of non-availability of any other revenue land has also been given by Tehsildar and Sub-Divisional Officer, Rudraprayag. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.</p>
---	---

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 3043 / 12-1021 दिनांक 06/03 / 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
 गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
 पौड़ी।

विषय- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के निर्माण हेतु 2.00 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

PROPOSAL NO. - FP/UK/OTHERS/44711/2020

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ.सी०/1056 दिनांक 01.11.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक-449/भूमिह०/2022-23 दिनांक 02.02.2023 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट- I के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no, I Justification provided for proposing a non site-specific project In forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category- wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van panchayat, Revenue, private, etc). The State Government is also requested to submit provide the land -use of the district and a proper justification ad to why the project could not be taken at any other place in the district	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 1. Certificate related for Category Wise Area of Land for District Rudraprayag is uploaded in online Proposal at additional documents and same is submitted in this letter at attachment no. 1. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. Attachment No-01
2	In reply to point no.2. Residential component is given in the component-wise break-up, which may not be allowed on forest land. State Govt. is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4 in part I	Residential building will not be constructed in the proposed land. Component wise breakup is revised and uploaded at para B 2.4 in part I. Document related to this query is attached in this letter at attachment 2. Attachment No-02
	In reply to point no 3, layout plan still not submitted .State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/patch separately	Layout plan and activity details of each patch is submitted in this letter at attachment no 3 and same is uploaded in online proposal at additional documents. Attachment No-03
	In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarification in this regard	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 4. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.

प्राप्त
 17/03/23
 व० सं०
 आ. का. कार्यालय

व० सं०
 आ.

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड
 कार्यालय
 प्राप्ति सं०. 641/81
 पत्रांक संख्या/27
 दिनांक/103/23
 पत्र किसको भेजा 9.11.21

5	<p>In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.</p>	<p>प्रकरण में हुये उल्लंघन के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.07.2015 (संलग्नक-4) को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया तत्पश्चात् वन भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिनांक 23.10.2015 (संलग्नक-5) के द्वारा संबंधित विभाग को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा इस कार्यालय को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक-372/भूमि विषयक-2015-16 दिनांक 04.11.2015 (संलग्नक-6) के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)-2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक-1304/12-1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक-7) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-8) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-9) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रूप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।</p>
6	<p>Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.</p>	<p>Proper and suitable non-forest land was searched at nearby village level, revenue level and private level, but proper and suitable land was not found available for establishment of polytechnic in nearby places. A meeting was held with the village heads of the nearby 4 gram panchayats (Kunda dankot, Kolu-Bhannu, Gorna and Tadag) for the availability of private land, but all the village heads said that land was not available, in relation to which all the 4 village heads signed certificate of non-availability of suitable private land was given. The certificate of non-availability of any other revenue land has also been given by Tehsildar and Sub-Divisional Officer, Rudraprayag. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.</p>

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (मूल सहित 04 प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या - /दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता,
रुद्रप्रयाग ।

सेवामें,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग ।

पत्रांक:- 449 / भूमि ह0 / 2022-23

दिनांक: 20 फरवरी
मार्च, 2023

विषय:- राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 02 हैक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (PROPOSAL NO- FP/UK/OTHERS/44711/2020) में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल सं० 8बी/यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0सी0/1056 दिनांक 01/11/2022 के द्वारा प्रेषित पत्र में बिन्दु संख्या-1 से बिन्दु संख्या 06 के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं की सूचना जिनका निराकरण कर इस पत्र से साथ प्रेषित किया जा रहा है।


अतः उक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

क्र० सं०	आपत्ति/कमियाँ	निराकरण
1.	In reply to point no,1 Justification provided for proposing a non site-specific project In forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category- wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van panchayat, Revenue, private, etc). The State Government is also requested to submit provide the land -use of the district and a proper justification ad to why the project could not be taken at any other place in the district	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 1. Certificate related for Category Wise Area of Land for District Rudraprayag is uploaded in online Proposal at additional documents and same is submitted in this letter at attachment no. 1. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. Attachment No-01
2	In reply to point no.2. Residential component is given in the component-wise break -up, which may not be allowed on forest land. State Govt. is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4in part I	Residential building will not be constructed in the proposed land. Component wise breakup is revised and uploaded at para B 2.4 in part I. Document related to this query is attached in this letter at attachment 2. Attachment No-02

	in reply to point no 3, layout plan still not submitted .State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/patch separately	Layout plan and activity details of each patch is submitted in this letter at attachment no 3 and same is uploaded in online proposal at additional documents. Attachment No-03
4	In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarification in this regard	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 4. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.
5	In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.	This query is replied at the level of Divisional Forest Office Rudraprayag.
6	Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.	Proper and suitable non-forest land was searched at nearby village level, revenue level and private level, but proper and suitable land was not found available for establishment of polytechnic in nearby places. A meeting was held with the village heads of the nearby 4 gram panchayats (Kunda dankot, Kolu-Bhannu, Gorna and Tadag) for the availability of private land, but all the village heads said that land was not available, in relation to which all the 4 village heads signed certificate of non-availability of suitable private land was given. The certificate of non-availability of any other revenue land has also been given by Tehsildar and Sub-Divisional Officer, Rudraprayag. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.

माननीय
कुं आ कां के ।
सं वं अवि
21/02/2023

भवदीय,

(विकास भट्ट)
समन्वयक / प्रधानाचार्य